मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- मज़दूरों से दुश्मनी निकाल रही हरियाणा सरकार 3
- पानी न हो तो प्यासे मरें, बरसे तो डूब कर
- भविष्य की राह:जन आयोग की सिफ़ारिशें एवं सुझाव 4
- रामदेव, रविशंकर के बाद अब आसाराम ने भी 'ठुकराया' नोबेल 5
- पूजा हत्या काण्ड: अपने इन्स्पेक्टर को बचा पायेगी पुलिस ? 8

वर्ष 29 अंक 13 फरीदाबाद, सोमवार 16-31 मई 2016 फोन : - 9999595632 2 ₹

जाट आरक्षण हिंसा पर बने जन आयोग का ज़ोर न्याय, सद्भावना, सुरक्षा पर

सरकार न घाव रोक सकी न मरहम लगा पाई, आरएसएस ने अपनी चलाई

बीती फ़रवरी में जाट आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा में हुई व्यापक हिंसा पर सद्भावना मंच द्वारा गठित जन आयोग का निष्कर्ष है कि राज्य सरकार न केवल उस दौर में सुरक्षा देने व शान्ति बनाये रखने में पूरी तरह असफ़ल रही बल्कि इस भीषण बर्बादी के उपरान्त क्षतिपूर्ति के उसके दावे भी खोखले नज़र आते हैं। 15 मई को जन आयोग ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट जारी की है। जबकि सरकार द्वारा काफ़ी पहले गठित प्रकाश सिंह कमेटी की पूरी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है, जिसमें उन्होंने खट्टर सरकार को बरी कर दिया है। वहीं, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित न्यायिक आयोग तो अभी काम शुरु भी नहीं कर पाया है। जन आयोग, जिसके सात सदस्यों ने आठ ज़िले में जाकर जन सुनवाई की, पर लगभग पचीस हज़ार का खर्च आया। सरकारी कमेटी/आयोग पर लाखों-करोड़ों खर्च होना तय है।

मज़दूर मोर्चा, रोहतक ब्यूरो

जन आयोग ने स्पष्ट रूप से माना है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार न्याय, सद्भावना, सुरक्षा एवं शान्ति को बहाल करने में वैचारिक रूप से सक्षम नज़र नहीं आती है। यद्यपि उस दौर की त्रासद घटनाओं के सम्बन्ध में करीब 2100 आपराधिक मुकदमे दर्ज किये गये हैं, तो भी न समाज के घाव भर रहे हैं और न ही क्षति पूर्ति का मरहम ही कारगर हो पा रहा है।

राज्य सरकार पर आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) की पकड़ को आयोग ने द्वैध शासन प्रणाली बताते हुए प्रशासन के छिन्न-भिन्न होने का जिम्मेदार ठहराया है। उल्लेखनीय है कि स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक हुआ करते थे और उनकी पुरानी वफ़ादारी आज भी उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर भारी पड़ रही है। द्वेध प्रशासन प्रणाली का एक रूप पुलिस विभाग में भी इंगित किया गया है। डीजीपी पुलिस बल का मुखिया होता है जबकि सीआईडी प्रमुख मुख्यमंत्री का आंख-कान बना होता है। लिहाज़ा दोनों ही कानून व्यवस्था, तफ़्तीश, तैनातियां, तबादलों इत्यादि में एक दूसरे के विरुद्ध काम करते देखे जाते हैं। आरक्षण आन्दोलन के दौरान दोनों के बीच समन्वय की कमी भी पुलिस की निष्क्रियता का एक कारण बनी।

एक खूनी आन्दोलन आमन्त्रित करने के बाद खट्टर सरकार ने आनन-फ़ानन में जाट आरक्षण बिल पास कर दिया। इस बीच इस बिल को अदालत में चुनौती भी दी जा चुकी है। आयोग का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा किये जा रहे हवन-यज्ञ या रोहतक में सरकारी 'सद्भावना' आयोजन, जिसमें रामदेव ने सामाजिक विद्वेष का ज़हर जम कर उगला, से हरियाणा में सद्भावना आने वाली नहीं। इसके लिये नये सिरे से नीतिगत कवायद, ठोस प्रशासनिक उपाय और विश्वसनीय राजनीतिक-सामाजिक पहल की आवश्यकता है। जन आयोग ने लोकतान्त्रिक पुलिस और उसके सक्षम नेतृत्व पर ज़ोर दिया है। इसके लिये, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पुलिस के काम-काज में सामुदायिक पुलिस और 'सत्ता निर्पेक्ष पुलिस' की अवधारणा समाहित की जाये।

जन आयोग ने एक नागरिक ट्रब्यूनल बनाने की भी सिफ़ारिश की है। यह ट्रब्यूनल भारी संख्या में दर्ज मुकदमों तथा क्षति पूर्ति के मामलों पर समयबद्ध निर्णय ले। जातिय पहचान के चिन्हों/संगठनों/संस्थाओं/धर्मशालाओं को सरकारी संरक्षण समाप्त करके विवेकशील मंचों को बढ़ावा दिया जाये। आयोग ने हर आरक्षित/सामान्य श्रेणी के अन्दर स्त्रियों के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने की सिफ़ारिश भी की है।

क्षति पूर्ति को लेकर व्यापक जन असन्तोष का हवाला देते हुए आयोग ने टिप्पणी की कि क्षति पूर्ति की प्रक्रिया को लाल-फ़ीताशाही के हवाले कर एक अन्तहीन तकनीकी/सिफ़ारशी कवायद बना दिया गया है। पीड़ितों के मुआवज़ा दावों को प्रथम दृष्टया सही मानकर अविलम्ब भुगतान होना चाहिये। सड़कों पर हफ़्तों फ़ंसे रहे ट्रक/लोग भी क्षति-पूर्ति के हकदार हों और यदि जरूरी हो तो इस सम्बन्ध में सरकार एक नया क्षति-पूर्ति कानून लाये।

सेना एवं केन्द्रीय सशस्त्र बलों के अंधाधुंध इस्तेमाल को लेकर भी जन आयोग ने सरकार की कठोर निंदा की है। आयोग ने माना है कि स्वचालित हथियारों से लैस सैनिकों को सिविल परिदृष्य में उतारना एक आत्मघाती कदम सिद्ध हुआ। इससे हिंसा को बढ़ावा मिला और लोग़ों का सेना पर से विश्वास भी डिग गया।

जन आयोग ने सरकार को ग्रामीण क्षेत्रो में बढ़ते कृषि व रोज़गार संकट का हल निकालने की चेतावनी दी है। ऐसे हिंसक आन्दोलन इस बात के भी द्योतक हैं कि केन्द्र सरकार के 'कौशल इन्डिया' और 'मुद्रा बैंक' जैसे रोज़गार परक प्रोजेक्ट अपर्याप्त हैं। आयोग ने पाया कि आरक्षण पाने के लिये बनी संवैधानिक प्रणाली का धैर्यपूर्वक इस्तेमाल कोई भी पक्ष नहीं कर रहा है, यहां तक कि सरकार भी।

सर्वसम्मति से दी गयी सिफ़ारिश में आयोग ने यह मांग भी की है कि अपनी रणनीतिक/ नियोजित चूकों के लिये खट्टर सरकार को सार्वजनिक रूप से अविलम्ब माफ़ी मांगनी चाहिये।

आन्दोलन के दौरान पानीपत ज़िले के गांव सिवाह के निवासियों ने हज़ारों आन्दोलनकारियों को पानीपत शहर पर धावा बोलने से रोक दिया था। इस अनूठी सामाजिक पहल का अध्ययन किया जाना चाहिये। जन आयोग के अनुसार सिवाह के निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के लिये पूर्वोपाय किये जा सकते हैं।

जन आयोग के सदस्य :- 1. वीएन राय पूर्व पुलिस महानिदेशक हरियाणा एवं पूर्व डायरेक्टर राष्ट्रीय पुलिस एकादमी हैदराबाद 2. टी के शर्मा पूर्व मंडल आयुक्त गुड़गांव, 3. शुभा, पूर्व कॉलेज प्राचार्य, 4. मेहर सिंह, पूर्व प्रधान वन संरक्षक, केरल, 5.राजीव गोदारा एडवोकेट पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट, 6.राम मोहन राय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 7. राजेन्द्र चौधरी पूर्व प्रोफ़ेसर एमडीयू रोहतक

ख़बर दार

खट्टर अपना नाम पृथ्वीराज चौहान रख लें तो क्या

खट्टर अपना नाम पृथ्वीराज चौहान रख लें तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में पूरी तरह असफ़ल रहे मनोहर लाल खट्टर अब तरह-तरह से संघ का खेल खेलते हुए जनता में स्थापित होने में प्रयासरत हैं। इस क्रम में उन्होंने एक नया हिन्दुत्ववादी पत्ता खेलते हुए केन्द्र को सुझाव भेजा कि दिल्ली की मशहूर अकबर रोड का नाम बदल कर महाराणा प्रताप रोड कर दिया जाये। इस संदर्भ में 'मज़दूर मोर्चा' की सलाह है कि खट्टर साहब अपना नाम भी बदल कर पृथ्वीराज चौहान रख लें। हालांकि तब भी हरियाणावासी, विशेषकर रोहतकवासी, उन्हें जयचन्द कह कर ही बुलायेंगे। आखिर आरक्षण आंदोलन की घोर विपत्ति के दिनों में वे ढूंढे नहीं मिल रहे थे। खट्टर से काल्पनिक साक्षात्कार प्रस्तुत है।

म.मो.-खट्टर साहब क्या वाकई आप अपना नाम बदलने जा रहे हैं ?

खट्टर-अपना नाम तो मैं पहले ही बदल चुका हूं। मनोहर लाल खट्टर से मनोहर लाल बनने के पीछे राज यही था कि लोग मुझे जातिवाद से ऊपर उठा मानें। पर आरक्षण आन्दोलन के दौरान तो मुझ पर शत-प्रतिशत पंजाबी का ठप्पा लग गया। नाम भी बदला और काम भी नहीं बना।

म.मो.-बैठे ठाले आपको अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड करने की बात कहां से सूझी ?

खट्टर-अरे भई आरक्षण आन्दोलन के दौरान हरियाणा में बहुत से लोग मुझे पाकिस्तानी कह कर चिढ़ाने लगे थे। मैंने सोचा महाराणा प्रताप के सहारे मैं हिन्दुस्तानी कहलाने लगूंगा।

म.मो.-लेकिन राणा प्रताप तो डट कर मुकाबला करने के लिये जाने जाते हैं। मुसीबत के समय उन्होंने साहस से अपनी प्रजा की रक्षा की थी। जबकि आपके अपने शहर रोहतकवासियों का भी मानना है कि घोर विपदा के समय आप उन्हें छोड़ कर नदारद हो गये थे। फ़िर आपकी राणा प्रताप से क्या तुलना ।

खट्टर-यह सब तो मैं भी जानता हूं। हरियाणा वाले तो मुझे जय चन्द ही मानेंगे। लेकिन मीडिया का जमाना है। सोचा, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। राणा प्रताप का शिगूफ़ा छोड़ूंगा तो मीडिया टाइगर तो बन ही जाऊंगा।

म.मो.-पर आपकी पार्टी की मोदी सरकार ने ही आपका प्रस्ताव तुर्त-फ़ुर्त ठुकरा दिया ? इस तरह मोदी को पशोपेश में डालना क्या आपकी सेहत के लिये ठीक होगा ?

खट्टर-अरे मैंने भी यह गुणा-भाग पहले ही कर लिया था। मोदी तो नाराज ही है क्योंकि हरियाणा में भाजपा का ग्राफ़ किस रसातल में पहुंच चुका है, यह मेरे मन्त्री ही सार्वजनिक रूप से बताते घुम रहे हैं। लिहाज़ा, मैंने सोचा कि क्यों न मोहन भागवत को ही पूरी तरह सेट कर लिया जाय। अकबर-राणा प्रताप से बढ़िया हिन्दुत्ववादी कोई कार्ड मुझे तो सूझा नहीं, तुम्हे सूझे तो बता देना।

म.मो.-बाबा रामदेव ने तो इससे भी बड़ा हिन्दुत्ववादी कार्ड रोहतक के सद्भावना-समरसता सम्मेलन में खेला था। आरक्षण के मुद्दे पर बंटे हिन्दू समुदायों को मुसलमानों के सिर काट लाने की ललकार से गोलबंद करने की बाबा की मुहिम कहीं आप से भारी न पड़ जाये ?

खट्टर-यही डर तो मुझे भी है। संघ वाले कहीं मुझे हटा कर रामदेव को ही मुख्यमंत्री न बना दें! तभी तो मैंने राणा प्रताप वाला कार्ड खेला।

म.मो.-वैसे पृथ्वीराज चौहान का नाम आप पर जंचेगा।

खट्टर-तुम भी मेरी टांग खींचने लगे। मैं कुछ भी कर लूं, रहूंगा खट्टर का ही खट्टर।

मोदी के लटके-झटके

कहते हैं भोर का सपना सच होता है - तो मित्रों आज भोर में मेरी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर भाई मोदी जी से हो गई लकालक डिजाईनर सफेद कुर्ता में सफेद दाड़ी बाल से सजे-धजे मिले - चेहरा आत्मविश्वास से लबरेज और हाथ में कई डिग्रियों का बंडल लपेटे ; मैंने झुक के अभिवादन किया और उन्होंने स्वीकृति में मुस्कुराते हुए सिर हिला कर जवाब दिया , तभी मेरी निगाह उनके हाथों में लिए बंडल पर जा कर टिक गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा - क्या देख रहे हो ! ये मेरी डिग्रियां हैं जो मैंने भारत सहित दुनियाँ के तमाम विश्वविद्यालयों से मँगवाई हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी तड़ से चिपका दूँगा , मैंने कहा सर लेकिन ये क्या उचित होगा ? उन्होंने प्रश्न खत्म होते ही तपाक से जवाब दिया ....बर्खुरदार ! दस लाख का सूट हो या ये डिग्रियाँ हों ये सब शासन चलाने में मेरे जरूरी अस्त्र हैं , अभी क्या ..... ? अभी तो मेरे अंडर गारमेंन्टस् से लेकर मेरे जूते चप्पल तक पर बहस होनी तय है , ये लटके झटके मेरी राजनैतिक रणनीति का अभिन्न हिस्सा है , आखिर भाई ! मसला पाँच साल का जो है , मुझे तो पब्लिक से किये वादों को भूलना और भूलाना दोनों मजबूरी भी है साथ ही जरूरी भी है , अब ! वो ऐसे तो भूलने से रहे तो आखिरकार ! कैसे ये संभव होगा..... ? तो नादान दोस्त ! ये वही अस्त्र-शस्त्र है जिनके जरिये मैं बड़ी से बड़ी चुनौतियों को अपने भोंपूओं के माध्यम से हल कर लूँगा , अब वो दौर लद चुका है जब हर बात में आईएसआई को चेंप दिया जाता था, खैर तुम छोटे लोग मुलाजिम टाईप हो जिन्दगी भर वही रहोगे, नहीं समझ सकते बदलते दौर की सियासत कैसे चलती है ? तभी मेरी छोटी बेटी ने सपने में अपने किसी दोस्त से लड़ाई के चलते नींद में ही मेरे गाल पे जोरदार झन्नाटेदार एक चाटा मारा और मैं तिलमिला कर उठ गया ...आगे की हकीकत का इस भोर के सपने से कोई ताल्लुक नहीं ..... ।

- मनीष तिवारी